इमरान खान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, मोदी से कहा- चलिये बात करते हैं

इस्लामाबाद-पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत के साथ अमन चाहते हैं। यहां के लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान की संभावना पर कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की जमीन का बाहर आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत देना हमारे हित में नहीं है। इमरान खान ने मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा देने पर कहा कि हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। जमात-उद-दावा प्रमुख पर पहले से ही शिकंजा कसा हुआ है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा ने कहा कि शांति के प्रयास एक तरफा नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा, हम नयी दिल्ली के संकेत के लिए भारत में होने वाले चुनावों (आम चुनावों) की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। पाक कहा कि चलिये बात करते हैं। मैं किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। कश्मीर का हल एक सैन्य समाधान नहीं हो सकता।

इससे पहले इमरान खान ने ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का शिलान्यास करते हुए कहा था कि उनका देश भारत के साथ 'मजबूत' और 'शिष्ट' संबंध चाहता है तथा प्रतिबद्धता के साथ दोनों देश कश्मीर सहित सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं।

इमरान ने कहा था, ''मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प और बड़े सपनों की जरुरत है। कल्पना कीजिए कि एक बार व्यापार शुरू हो जाता है, हमारा रिश्ते सुधर जाते हैं तो दोनों देशों को कितना फायदा हो सकता है।'

राफेल की तरह ही भारत के खिलाफ एक अपराध है नोटबंदी-राहुल गांधी

नई दिल्ली-कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नोटबंदी राफेल सौदे की तरह भारत के खिलाफ अपराध और एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि जब पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन नोटबंदी के फैसले से ''असहमत'' थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी ऐसा ही किया था।

उन्होंने ट्वीटर पर कहा, 'राफेल (सौदे) की तरह नोटबंदी भारत के खिलाफ एक अपराध और एक बड़ा घोटाला था। पर्रिकर ने अपनी खाल बचाने के लिए राफेल से दूरी बनाये रखी। श्री सुब्रमण्यन नोटबंदी के मामले में ऐसा ही कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया जब वह इतने असहमत थे? चिंता मत करो भारत, दोषियों का पता लगाकर उन्हें दंडित किया जाएगा।'

अमेरिका ने इस साल पाकिस्तान की तीन अरब डॉलर की सहायता राशि रोकी

वाशिंगटन-अमेरिका ने इस साल पाकिस्तान को सुरक्षा मद में दी जाने वाली तीन अरब डॉलर की सहायता राशि को देने से टाल दिया। आतंकी समूहों पर लगाम लगाने में विफल रहने पर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गयी। यह आंकड़ा पूर्व में ट्रंप सरकार द्वारा उल्लेखित 1.3 अरब डॉलर से बहुत अधिक है। पीटीआई- सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभिन्न माध्यमों से किये गए भुगतान के हालिया संकलन से तीन अरब डॉलर का आंकड़ा प्राप्त हुआ है। हालांकि, अब तक तीन अरब डॉलर की निलंबित राशि को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन यह इस महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहे गए 1.3 अरब डॉलर और पिछले सप्ताह पेंटागन द्वारा बताये गए 1.66 अरब डॉलर से बहुत अधिक है। ऐसा समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच हाल में ट्विटर पर हुई जंग के बाद अमेरिकी सरकार की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों का संकलन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस महीने कहा था कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए अमेरिका की ओर से अरबों डॉलर खर्च किये जाने के बावजूद पाकिस्तान ने उनके देश के लिए कुछ भी नहीं किया। खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें 'ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए।'

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी माना, दाऊद इब्राहीम को वापस लाना मुश्किल

नई दिल्ली-जम्मू कश्मीर में असंतोष के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुये केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि इस महीने होने वाले पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में राज्य के 90 प्रतिशत लोग हिस्सा लेंगे। बहरहाल, गृहमंत्री ने पाकिस्तान में छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन एवं 1993 मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के सरगना दाऊद इब्राहीम को वापस लाने में अड़चनों को स्वीकार किया।

सिंह ने कहा जम्मू-कश्मीर में 1995 में करीब 6,000 आतंकी घटनाएं हुईं और 2017 में यह घट कर 360 पर आ गई। गृहमंत्री ने 'एचटी लीडरशिप सम्मिट' में यहां कहा, ''हमने हमेशा पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का प्रयास किया है। लेकिन देश (पाकिस्तान) अपना तौर-तरीका नहीं बदल रहा है। वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रायोजन करना जारी रखे है।''

जम्मू-कश्मीर में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों का हवाला देते हुये गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के 90 प्रतिशत लोग चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होंगे जिसे मौजूदा सरकार ने लंबे समय के बाद शुरू की है। स्थानीय निकायों में भाजपा के कई प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि हाल में पश्चिम बंगाल में आयोजित पंचायत चुनाव में 43 प्रतिशत प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये और ऐसी चीजें असामान्य नहीं है।

उन्होंने भाजपा और पीडीपी के बीच टूट चुके गठबंधन के बारे में कहा कि पिछले राज्य विधानसभा चुनाव के जनादेश का सम्मान करते हुये दोनों दलों ने हाथ मिलाया लेकिन ''प्रयोग सफल नहीं हुआ।'' सिंह ने कहा कि कुछ साल पहले तक नक्सलवाद राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती था लेकिन उसपर एक हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। कुछ संस्थानों पर भाजपा के कब्जे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर सिंह ने कहा कि ये 'आरोप निराधार' हैं। उन्होंने कहा, ''उन्हें (गांधी) कम से कम एक उदाहरण देना चाहिए जिसमें यह हुआ हो। हमने हमेशा देश में हर संस्थान की गरिमा बनाए रखा है।''

सरकार ने किसान मजदूर विरोधी नीतियां नहीं बदलीं तो सरकार बदल देंगे- सीटू

नई दिल्ली-किसान एवं मजदूर संगठनों की वाम समर्थित रैली में बुधवार को पारित प्रस्ताव में केन्द्र सरकार से किसानों और कामगारों के हितों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही नीतियों को बदलने का आह्वान करते हुये आगाह किया गया है कि अगर नीतियां नहीं बदलीं तो सरकार बदल दी जायेगी। वाम दलों के मजदूर संगठन सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित किसान मजदूर संघर्ष रैली में विभिन्न राज्यों से आये किसानों और मजदूरों को संबोधित करते हुये किसान सभा के महासचिव हनन मोल्ला ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से परेशान किसान और कामगार संगठनों ने एक मांग पत्र जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि रोजमर्रा की वस्तुओं की बेलगाम कीमतों, खाद्य वितरण प्रणाली की ध्वस्त होती व्यवस्था और रोजगार के सिमटते दायरे से किसान, मजदूर और युवाओं का जीवन अंधकारमय हो गया है। संगठनों द्वारा पारित मांगपत्र में महंगाई पर नियंत्रण करने, खाद्य वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने, युवाओं को रोजगार के उचित अवसर दिलाने, मजदूरों के लिए 18 हजार रुपये मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करने, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव नहीं करने, किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने और खेतिहर मजदूरों और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की गयी है।

रैली में दूरसंचार, रेल, डाक और परिवहन सहित अन्य महकमों के कर्मचारी संगठनों, किसान संगठन और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि रामलीला मैदान में एकत्र हुये। इसके बाद हनन मोल्ला और किसान सभा के तपन सेन सहित अन्य संगठनों के नेताओं की अगुवाई में इन लोगों ने रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक पैदल मार्च किया। संसद मार्ग पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुये सेन ने कहा कि समाज के सभी वर्गों में लगातार बढ़ते आक्रोश की वजह से ही इस रैली में लाखों लोग दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और कामगारों ने अब संकल्प लिया है कि अगर सरकार ने गलत नीतियां नहीं बदलीं तो वे सरकार बदल देंगे।

रैली में माकपा नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, वृंदा करात, नीलोत्पल बसु और सुभाषिनी अली के अलावा भाकपा के डी राजा सहित अन्य नेताओं ने भी शिरकत की। रैली का स्वरूप गैरराजनीतिक होने के कारण इसमें हिस्सा लेने वाले राजनेताओं ने मंच के बजाय जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करायी। बाद में येचुरी ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के चुनाव पूर्व वादे चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब तक अधूरे रहे।उन्होंने कहा, 'अच्छे दिन तभी आयेंगे जब मोदी सरकार जायेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को गिराना ही एकमात्र समाधान है।' येचुरी ने बताया कि वामदल अगले सप्ताह से देशव्यापी संयुक्त आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी रूपरेखा जल्द घोषित की जायेगी।

पाक विदेश मंत्री का शर्मनाक बयान, कहा- इमरान की गुगली में फंस गया भारत

इस्लामाबाद-पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे के शिलान्यास कार्यक्रम में भारतीय सरकार की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक गुगली फेंकी। कुरैशी की यह टिप्पणी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के एक दिन पहले दिए गए बयान पर आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करने की संभावना को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पाकिस्तान जब तक भारत के खिलाफ सीमा-पार से अंजाम दी जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तब तक बातचीत संभव नहीं है।

पाकिस्तान ने इससे पहले बुधवार के कार्यक्रम में स्वराज को भी आमंत्रित किया था। लेकिन स्वराज ने पूर्व प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए करतारपुर साहिब आने में असमर्थता जताई थी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों- हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कुरैशी ने कहा कि करतारपुर सीमा का खुलना क्रिकेटर से नेता बने खान की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। बृहस्पतिवार को खान नीत सरकार ने आम चुनावों को जीतने के बाद से अपने शुरूआती 100 दिन पूरे कर लिए। कुरैशी ने क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इमरान ने एक गुगली डाली और भारत ने दो मंत्रियों को पाकिस्तान भेज दिया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक-रवि कुमार पोत्दार, ७२/७४, सुयश विहार, भमोरी दुबे, इन्दौर से प्रकाशित एवं आर्टटेक ग्राफिस, ८६४/९, नेहरु नगर, इन्दौर म०प्र० से मुद्रीत
प्रधान संपादक-रवि कुमार पोत्दार आर.एन.आई. नम्बर-१२७८२/२००३ e-mail- censortimes@ hotmail.com Mob No-9926631707